IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

शिक्षा में कदाचार और अनाचार रूशैक्षणिक संस्थानों की स्थिति

डॉ0 बामेश्वर प्रसाद

व्याख्याता, समाजषास्त्र विभाग,पैरू महतो सोमरी महाविद्यालय बिहारषरीफ ,नालंदा, बिहार
(पाटलिपुत्रा विष्वविद्यालय, पटना, बिहार, भारत)

यह सर्वविदित है कि शिक्षा चाहे प्राथमिक हो या उच्चतर व्यवहारिक हो या अध्यात्मिकए औपचारिक हो या अनौपचारिक लोगों में संस्कार गढ़ती है। यह एक जीवन शैली हैए जिसके सहारे लोग व्यक्ति बोध तथा सामजिक दायित्व का ज्ञान प्राप्त करते है। वृहतर परिपेक्ष्य में शिक्षाजीवन जीने के आयाम खोलती है।शिक्षा के इस आयाम पर विचार करने से यह एहसास होता है कि लॉर्ड मेकाले से लेकर स्वतन्त्र भारत में जितनी भी शिक्षा नीतियाँ बनी लोगों को मुक्ति करने के बजाय बंधन युक्त करती रही है। शिक्षा का सीधा संबंध देश एवं समाज की जीवनधारा से होता है। अतः बार.बार शिक्षा के नाम पर किये जा रहे प्रयोग का सीधा प्रहार देश के बच्चों पर पड़ता है जो प्रकारान्तर से राष्ट्रहीत के प्रतिकूल ही होती है वर्तमान नई शिक्षा पद्धति इसी संदर्भ की एक विशेष कड़ी है। यों तो स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा के विकास और आमूल सुधार हेतू अनेक प्रयास किसे गये। तथापि शैक्षिणिक संस्थानों की स्थिति अधिक शर्मनाक और दुःखद मोड़ पर पहुँचती जा रही हैं। उसमें भी उच्चतर शिक्षा कि स्थिति तो और भी नाजूक होती हा रही है।

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में आमूल परिवर्तन हेतू सरकार ने 1948.49 में डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णण के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया जिसमें कई ठोस सिफारिशे की। इसी आयोग कि सिफारिश के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बराबर किया गया। वर्ष 1964.66 में डॉ० कोठारी कि अध्यक्षता में पुनः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया गया। जिसने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सन् 1969 में वि०वि० के लिय मुबई वि०वि० के तत्कालीन कुलपति डॉ० पी०बी० गजेन्द्र गडकर और अन्य महाविद्यालयों के लिये गोरखपुर वि०वि० के कुलपति डॉ० पी०टी० चांडी कि अध्यक्षता में अलग.अलग राष्ट्रीय शिक्षा समितियाँ गठित हुई जिन्हें बाद में मिलाकर डॉ० एस०एन० सेन कि अध्यक्षता मे नया शिक्षा आयोग बनाया गया जिसके आधार पर ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नया वेतनमान लागू किया गया तदोपरांत 1983.85 में उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए डॉ० रईस अहमद की अ यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग और वेतन पुनरीक्षण हेतु जयपुर वि०वि० के प्रख्यात रासायनशास्त्री प्रो० आर० सी० मेहरोत्रा कि अ यक्षता में एक अलग आयोग गठित किया गया। जिनकी सिफारिशों के आधार पर जनवरी 1986 से ही सभी शिक्षकों को नया वेतनमान दिया गया है। बिहार में यह कागज पर ही लागू हुआ है।इन विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों कि सिफारिशों का भी बिहार पर कोई विशेष असर नहीं हो सका है। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि नालंदा और विक्रमशीला जैसे विख्यात वि०वि० के माध्यम से संपूर्ण संसार में ज्ञान कि ज्योति प्रज्वलित करने वाली भगवान् बुद्ध और गौतम कि धरा आज स्वयं ही अज्ञानता के गर्त में डूबती जा रही है और गौरवशाली अतीत से विमुक्त होकर आधारहीन मोड़ पर पहुंचने लगी है।

बिहार के लगभग सभी वि०वि० एवं महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति और उनमें हो रहे निरंतर गुणात्मक हास अत्यंत ही चिंता के कारण है। न पठन पाठन का अनुकूल वातावरण हैए न अनुशासनए न वितीय अनुशासन हैए न उतम गुरु शिष्य संबंध। न लोगों में लोक दायित्व हैए न समर्पण भावए न उत्तम प्रशासन है न कार्य निष्पादन कि स्वायतताए न समाज कि चिंताए न देश कि न छात्रों एवं शिक्षकों की हितों की रक्षा कि। चारो तरफ उपेक्षा का वातावरण है। सर्वत्र अराजकता है। बिहार के सभी शैक्षिणिक संस्थान वितीयए प्रशासनिक और शैक्षिणिक दृष्टि से जर्जर हो चुके है। इनकी स्थिति आज लाइलाज लगने लगी है। जिनका सर्वाधिक प्रभाव शिक्षको एवं छात्रों पर ही पड़ रहा है न वि०वि० अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की पढ़ाई। न शिक्षको को समय पर पुरा वेतन मिलता है न छात्रों का नित्य बदलते

पाठ्यक्रमों पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तके और न प्रयोगशाला उपकरण। न परीक्षायें समय पर होती है। न उतर पुस्तिकाओं का न्यायपूर्ण व निष्पक्ष मूल्यांकनए न स्वच्छ परीक्षायें होती है न समय पर परीक्षाफलों क प्रकाशन ही।
डॉ० रइस अहमद राष्ट्रीय शिक्षण आयोग.2 की रिपोर्ट के अनुसारए श्बहुव्यापी अनभूति है कि जितना हास शिक्षण व्यवसाय कि प्रतिष्ठा का हुआ हैए किसी अन्य व्यवसाय का नहीं। यह सत्य है कि वर्तमान स्थिति अति असंतोषप्रद है। जिसके लिये तुरंत उपचार किये जाने चाहिए। इसी प्रकार यूनेस्को के सांतवे दशक में अंतर सरकार सम्मेलन में भी यह सिफारिश कि गयी। शिक्षको के कार्य की स्थितियाँए उन्हें दिये जाने वाले वेतन तथा अन्य जीवन सुविधाएँ पर्याप्त नहीं है। आयोग कि यह भी धारणा है कि समाज में एक शिक्षण को जितनी मान्यता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है।आज बिहार के सारे संस्थान रोगग्रसिता है। प्रश्न उठता हैए इतनी जर्जरता के आखिर कारण क्या है ६ मेरी यह मानता है कि इसके अनेक कारण है किंतु इसके लिय शिक्षकए छात्रए अभिभावकए वि०वि० पदाधिकारीए राजनेता और सरकार सभी जबावदेह है। किन्ही एक को पूरी तरह जबावदेह ठहराना घोर अन्याय और एकपक्षीय होगा। फिर भी सरकार एवं राजनेताओं का दोष सर्वाधिक है।हलांकि इस कटु सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वि०वि० राजनीतिक में लगे कतिपय शिक्षको ने बिहार की उच्च शिक्षा को बर्बाद करने में कम योगदान नहीं किया है। कई पुराने द्राणाचार्यों ने ही अपने चहते अर्जुनो के कारण अनेको एकलव्यों की प्रतिभाओं को कठित कर दिया है। कई धाकड़ विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य भी इस दुष्प्रभाव से बच नहीं सके।
रइस अहमद आयोग 1985 ने भी अपने द्वितीय रिपोर्ट में यह शिकायत कि है कि श्अधिकांश शिक्षक पूरी दक्षिता और प्रतिभा रखते हुये भी अपने कार्य और दायित्व से कतराते है। पठन.पाठन में निरसता प्रदर्शित करते है। कई ऐसे है जो कम मेधावी है और प्रतिभाओं को दमित कर पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने में सफल हो गये है। प्राइवेट ट्यूशन को प्रोत्साहित करते है और उसी मे रमे रहते है जिससे शिक्षको कि सामाजिक प्रतिष्ठा में आँच आई है। छात्रों के दिल ने अपने गुरूजनो के प्रति श्रद्धा में कमी आई है। बिहार में तो यह सामान्य बात होती जा रही है। कई ऐसे लोग भी है जो अपना निजी हित साधने के लिए अनुशासन हीन छात्रों एवं समाज विरोधी तत्वों का सहारा लें उन्हे संरक्षण दें। परिसर मे अशांति कराते है। संस्थान और अपने पद की गरिमा का तनिक भी ख्याल नहीं करतेए जो सचमुच भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र भी इस खराब स्थिति के लिए कम जबावदेह नहीं है। यहाँ बहुतायत छात्र पठन. पाठन में अपेक्षाकृत कम ध्यान देते है। या तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते या फिर लगाते भी है तो काफीकम कई प्रकार कि गलत और बुरी आदते पकड़ते जाते है। बिना परिश्रम के ही कदाचार पूर्ण परीक्षा के माध्यम से सर्वाधिक अंको से उतीर्ण होना चाहते है। दुर्भाग्यवश कतिपय शिक्षिकों की भी इस भागीदारी रहती है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण प्रतिभापलायन तेजी से हो रहा है। जिससे भावी पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है जो बिहार के लिए घातक है।
अभिभावकों कि भी इसमें कम भूमिका नहीं रहती है। ऐसे अभिभावको की आज संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जा अपने बच्चों को येन केन प्रकारेण उँची.उँची उपाधिया और सर्वाधिक अंक दिलाना चाहते है। छात्र से अभिभावक ही ज्यादा सक्रियता और उत्साह प्रदर्शित करते है।
महाविद्यालय के प्रधानाचार्यो वि०वि० के कर्मचारियों एवं समस्त अधिकारियो ; कुछ अपवादों को छोड़कार द्ध का तो इस दुर्दशा में विशेष योगदान है। अधिकांश प्रधानाचार्य तो महाविद्यालयों कि संपति को अपनी निजी संपति समझने लगे है। प्रायः मुख्यालय में नहीं रहते। कोई न कोई ठोस बहाना बजाकर मुख्यालय से बाहर रहते है और नाजायज यात्रा भत्ता लेते है। जो शैक्षिणिकए वितीय तथा प्रशासनिक सभी दृष्टि से घातक है। अनियमित और अवैद्य नियुक्तियाँ कर कोष का दुरुपयोग करते है। सभी शिक्षकों एवं छात्रों पर समान भाव नहीं रहते। वि०वि० प्रशासन का आलम यह है कि सभी भ्रष्टाचार में अकांठ डूबे रहते है। बिना दान दक्षिणा के तो संचिकायें निष्पादित होती ही नहीं है। चाहे कार्य जितना भी जरूरी क्यों न हो। सचिवालय और वि०वि० में अब कोई अन्तर रह ही नहीं गया है। यात्रा भत्ता के नाम पर बहुत बड़ी राशि कि लूट मची रहती है। अतिसाधारण कार्य डाक के द्वारा नहीं वरन विशेष दूत के माध्यम से और अति विशिष्ट कार्य विशेष दूत के बजाय डाक से संपादित कराये जाते है। लगता हैए मानव न किसी का कोई दायित्व है न नियंत्रण। इसी प्रकार कई कुलपतियों द्वारा बड़े पैमाने पर अस्वीकृत पदों पर शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों कि नियुक्ति कि जाती है और उसमें भी राधाकृष्णन आयोग और सेन आयोग कि सिफारिशों के आधार पर निर्धारित मानदंडों को ताक पर रखकर। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है कि बिहार के वि०वि० कि स्थिति कई पूर्व कुलपतियों के अधिकारों के दुरूपयोग के कारण हुई है। उसकी कीमत आज सभी को चुकानी पड़ रही है।
अन्त मेंए सर्वाधिक दोषी सरकार है। सेन आयोग कि तरह ही रईस अहमद आयोग ने यह स्वीकार किया है कि राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारों कि उपेक्षा कि स्थिति में गिरावट आयी है। शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को समय पर वेतन न देनेए वि०वि० एवं महाविद्यालयों के दैनिक कार्यो में बढ़ रहे राजनीतिक हस्तक्षेपए और उनकी स्वायतता पर किये जा रहे नियमित कुठारावात के प्रति इन राष्ट्रीय शिक्षा आयोगों ने काफी चिंता व्यक्त कि है। आज बिहार की सभी संस्थानों कि बदहाली और उच्च शिक्षा में गुणात्मक हास दोनों के लिए सरकार अधिक दोषी है। आज सभी शिक्षको एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए मुहताज रहना पड़ रहा है। अन्य सुविधाओं

कि तो बात ही अलग है। वित्तीय अनुशासन के नाम पर वि० वि० के बजट को बेरहमी से काट लिया जाता है। स्वीकृत राशि से भी कम और वह भी अनियमित रूप से सरकार द्वारा विमुक्त कि जाती है। यह उपेक्षात्मक प्रवृत्ति विगत वर्षों में तीव्रतर ही होती जा रही हैए जो सचमुच दुर्भाग्यपूर्णए अन्यायपूर्ण और विभेदात्मक है। सरकार द्वारा शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय को अनुत्पादक समझा जाना लगा है। आश्चर्य होता है कि इस नासमझी पर सरकार यह भूल जाती है कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों कि कितनी बड़ी भूमिका होती है। यह खेद जनक है कि देश के राजनीतिज्ञों एवं सरकार के विभिन्न शिक्षकेत्तर सरकारी विभागों ;यथाए स्वास्थ्यए चिकित्साए वित्तए कल्याणए कृषिए सिंचाईए उद्योगए लोकनिर्माण विभाग आदिद्ध में कुट.कुट कर व्याप्त भष्ट्राचार नजर नहीं आते किन्तु कितनी विचित्र बात है कि इन शैक्षणिक संस्थानो में कार्यरत लोगों को समय पर पुरा वेतन भी नहीं मिलेए छात्रों को पुस्तके और प्रयोगशाला उपकरण न उपलब्ध हो। क्या यही दिन देखने के लिए भारत में ष्कल्याणकारी राज्यष और ष्समाजवादी समाज की स्थापना कि थी आज कि स्थिति तो यह है कि कुलपतियों को भी प्रतिमाह वित्तीय अनुदान के लिए सचिवालय मे चक्कर लगाना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि कलपति का पद कितना गरिमामय है। किन्तु इस कुव्यवस्था के सामने उन्हें भी घुटने टेकने पड़ते है। इस गरिमा को गिराने में एक मात्र हाथ सरकार और राजनेताओं का है।शिक्षक संघ और छात्र संगठन भी विभिन्न राजनीतिक दलों में संबद्ध होकर अधिकांश मुद्दो पर शिक्षकों एवं छात्रों के व्यापक हितों को ताक पर रख देते है । प्रायः इनका नेतृत्व भी संकिर्णताओं में बंध जाता है ।

महाविद्यालय के प्रधानाचार्यो वि०वि० के कर्मचारियों एवं समस्त अधिकारियो ; कुछ अपवादों को छोड़कार द्ध का तो इस दुर्दशा में विशेष योगदान है। अधिकांश प्रधानाचार्य तो महाविद्यालयों कि संपति को अपनी निजी संपति समझने लगे है। प्रायः मुख्यालय में नहीं रहते। कोई न कोई ठोस बहाना बजाकर मुख्यालय से बाहर रहते है और नाजायज यात्रा भत्ता लेते है। जो शैक्षिणिकए वितीय तथा प्रशासनिक सभी दृष्टि से घातक है। अनियमित और अवैद्य नियुक्तियाँ कर कोष का दुरुपयोग करते है। सभी शिक्षकों एवं छात्रों पर समान भाव नहीं रहते। वि०वि० प्रशासन का आलम यह है कि सभी भ्रष्टाचार में अकांठ डूबे रहते है। बिना दान दक्षिणा के तो संचिकायें निष्पादित होती ही नहीं है। चाहे कार्य जितना भी जरूरी क्यों न हो। सचिवालय और वि०वि० में अब कोई अन्तर रह ही नहीं गया है। यात्रा भत्ता के नाम पर बहुत बड़ी राशि कि लूट मची रहती है। अतिसाधारण कार्य डाक के द्वारा नहीं वरन विशेष दूत के माध्यम से और अति विशिष्ट कार्य विशेष दूत के बजाय डाक से संपादित कराये जाते है। लगता हैए मानव न किसी का कोई दायित्व है न नियंत्रण। इसी प्रकार कई कुलपतियों द्वारा बड़े पैमाने पर अस्वीकृत पदों पर शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों कि नियुक्ति कि जाती है और उसमें भी राधाकृष्णन आयोग और सेन आयोग कि सिफारिशों के आधार पर निर्धारित मानदंडों को ताक पर रखकर। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है कि बिहार के वि०वि० कि स्थिति कई पूर्व कुलपतियों के अधिकारों के दुरूपयोग के कारण हुई है। उसकी कीमत आज सभी को चुकानी पड़ रही है।

कदाचार और अनाचार के वातावरण में ईमानदारी और सत्यता तो छूमन्तर की तरह गायब हो जाते हैं। इनके स्थान पर केवल बेईमानी और कपट का प्रचार और प्रसार हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कदाचार और अनाचार का केवल दुष्प्रभाव ही होता है इसे दूर करना एक बड़ी चुनौती होती है।कदाचार और अनाचार के द्वारा केवल दुष्प्रवृत्तियों और दुष्चरित्रता को ही बढ़ावा मिलता है। इससे सच्चरित्रता और सद्प्रवृत्ति की जड़ें समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है किकदाचार और अनाचार की राजनैतिकए आर्थिकए व्यापारिकए प्रशासनिक और धार्मिक जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो गई हैं कि इन्हें उखाड़ना और इनके स्थान पर साफ सुथरा वातावरण का निर्माण करना आज प्रत्येक राष्ट्र के लिए लोहे के चने चबाने के समान कठिन हो रहा है।

कदाचार और अनाचार के वातावरण में ईमानदारी और सत्यता तो छूमन्तर की तरह गायब हो जाते हैं। इनके स्थान पर केवल बेईमानी और कपट का प्रचार और प्रसार हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कदाचार और अनाचार का केवल दुष्प्रभाव ही होता है इसे दूर करना एक बड़ी चुनौती होती है।कदाचार और अनाचार के द्वारा केवल दुष्प्रवृत्तियों और दुष्चरित्रता को ही बढ़ावा मिलता है। इससे सच्चरित्रता और सद्प्रवृत्ति की जड़ें समाप्त होने लगती हैं। यही कारण है किकदाचार और अनाचार की राजनैतिकए आर्थिकए व्यापारिकए प्रशासनिक और धार्मिक जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो गई हैं कि इन्हें उखाड़ना और इनके स्थान पर साफ सुथरा वातावरण का निर्माण करना आज प्रत्येक राष्ट्र के लिए लोहे के चने चबाने के समान कठिन हो रहा है। कदाचार और अनाचार दो शब्द हैंए भ्रष्ट और आचार। भ्रष्ट का अर्थ है. बुरा या बिगड़ा हुआ और आचार का अर्थ है आचरण।कदाचार और अनाचार का शाब्दिक अर्थ हुआ ृ वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक और अनुचित है।

सारांश रू.

शैक्षणिक संस्थानों में आमूल परिवर्तन हेतू सरकार ने 1948.49 में डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णण के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया जिसमें कई ठोस सिफारिशे की। इसी आयोग कि सिफारिश के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बराबर किया गया। वर्ष 1964.66 में डॉ० कोठारी कि अध्यक्षता में पुनः राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया गया। जिसने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सन् 1969 में वि०वि० के लिय मुबई वि०वि० के तत्कालीन कुलपति डॉ० पी०बी० गजेन्द्र गडकर और अन्य महाविद्यालयों के लिये गोरखपुर वि०वि० के कुलपति डॉ० पी०टी० चांडी कि अध्यक्षता में अलग.अलग राष्ट्रीय शिक्षा समितियाँ गठित हुई जिन्हें बाद में मिलाकर डॉ० एस०एन० सेन कि अध्यक्षता मे नया शिक्षा आयोग बनाया गया जिसके आधार पर ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नया वेतनमान लागू किया गया तदोपरांत 1983.85 में उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए डॉ० रईस अहमद की अ यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग और वेतन पुनरीक्षण हेतु जयपुर वि०वि० के प्रख्यात रासायनशास्त्री प्रो० आर० सी० मेहरोत्रा कि अ यक्षता में एक अलग आयोग गठित किया गया। जिनकी सिफारिशों के आधार पर जनवरी 1986 से ही सभी शिक्षकों को नया वेतनमान दिया गया है। बिहार में यह कागज पर ही लागू हुआ है।इन विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगों कि सिफारिशों का भी बिहार पर कोई विशेष असर नहीं हो सका है। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि नालंदा और विक्रमशीला जैसे विख्यात वि०वि० के माध्यम से संपूर्ण संसार में ज्ञान कि ज्योति प्रज्वलित करने वाली भगवान् बुद्ध और गौतम कि धरा आज स्वयं ही अज्ञानता के गर्त में डूबती जा रही है और गौरवशाली अतीत से विमुक्त होकर आधारहीन मोड़ पर पहुंचने लगी है।

सन्दर्भ पुस्तक

1. हिन्दुस्तान, 22 दिसम्बर 1987 पृष्ठ संख्या 5
2. आज 8 फरवरी 1992 पृष्ठ संख्या 9
3. आज 21 जून 2000 पृष्ठ संख्या 5
4. हिन्दुस्तान 7 सितम्बर 2001 पृष्ठ संख्या 8
5. आज 9 अक्टुबर 2001 पृष्ठ संख्या 4
6. आज 28 दिसम्बर 2000 पृष्ठ संख्या 8
7. योजना 1.15 सितम्बर 1990 पृष्ठ संख्या 27.29
8. नवभारत टाईम्स 27 मार्च 1993 पृष्ठ संख्या 4
9. आज 30 मार्च 1988 पृष्ठ संख्या 4
10. हिन्दुस्तान 5 अप्रैल 1988 पृष्ठ संख्या 5
11. हिन्दुस्तान 16 फरवरी 1988 पृष्ठ संख्या 5
12. दैनिक जागरण 27 अक्टुबर 2002 पृष्ठ संख्या 8
13. आज 24 अक्टुबर 2002 पृष्ठ संख्या 4
14. हिन्दुस्तान 11 अगस्त 1987 पृष्ठ संख्या 5
15. पाटलीपुत्र टाइम्स 17 सितम्बर 1986 पृष्ठ संख्या 5
16. आज 16 जून 2002 पृष्ठ संख्या 4
17. आज 17 जून 2002 पृष्ठ संख्या 4